

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated 20-5-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 6.450 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Karanprayag-Nanisain-Kandara to kedarkot" in Chamoli district falls within jurisdiction, Kandara & kot village (s) in Karanprayag & Tharali tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.450 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Kandara & kot' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 20.5.2015 at time 17.00 hrs at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 7.500 hect for the construction of "Karanprayag-Nanisain-Kandara to kedarkot" and forest land 6.450 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag & Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 20.5.2015

**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**

जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.द्यो. में कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे. सिविल भूमि, 0.350 हे. वन पंचायत भूमि, 5.320 हे. आरक्षित वन भूमि एवं मक. डि. योज. हेतु 0.500 हे. भूमि कुल 6.450 हे. भूमि का लो. नि. वि. को हस्तान्तरण।, कार्यालय उप जिलाधिकारी, धराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, धराली

उपखण्ड धराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.350 हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि, मक. डि. योज. हेतु 0.500 हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 6.450 हे. वन भूमि) का लो. नि. वि. गौ. चर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धराली) की दिनांक 16-05-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री शैलेंद्र सिंह जी उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री शिवानन्द सुमन उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री नरिन्द्र प्रताप सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्री राम लाल बी.डी.ओ. सी.ओ. क्षेत्र पंचायत सदस्य

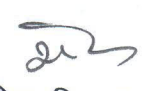
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.द्यो. में कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे. सिविल भूमि, 0.350 हे. वन पंचायत भूमि, 5.320 हे. आरक्षित वन भूमि एवं मक. डि. योज. हेतु 0.500 हे. कुल 6.450 हे. परियोजना कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट मो. मार्ग लो. नि. वि. गौ. चर

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

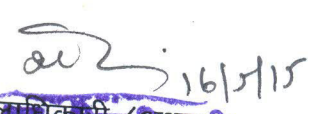
वर्कनाम वन प्रभाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, _____ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ~~पराली~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~कणारा से केरा जोर मोटा बाग~~ परियोजना के निर्माण हेतु 6:450 हे. हे० वन भूमि को नि:प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- विशद
 जनपद- बनारस

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बनारस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- विशद
 जनपद- बनारस

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत आ. सु. धो. में कर्णप्रयाग-नैनीताल मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे० सिविल भूमि 0.350 हे० वन पंचायत भूमि 5.320 हे० आरक्षित वन भूमि एवं भूक उपयोग हेतु 0.500 हे० कुल 6.450 हे० वन भूमि का लो. नि. वि. की हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत कण्डारा से केदारकोट तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु (5.320 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, भूक उपयोग हेतु 0.500 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 6.450 हे० वन भूमि) का लो. नि. वि. गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 08/10/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 1- | श्री <u>के. ए. रेजी</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>शिवराम सुमन</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री <u>मोहन लाल</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री <u>विजय सिंह</u> | डी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत आ. सु. धो. में कर्णप्रयाग-नैनीताल मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे० सिविल भूमि 0.350 हे० वन पंचायत भूमि 5.320 हे० आरक्षित वन भूमि एवं भूक उपयोग हेतु 0.500 हे० कुल 6.450 हे० वन भूमि परियोजना कर्णप्रयाग नैनीताल मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग, लो. नि. वि. गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

वैदनाथ वन प्रभाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कठारा परिक्षेत्र के अन्तर्गत कठारा से केदारकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.450 हे० वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कठारा
जनपद— नमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कठारा
जनपद— नमोली

शकुन्तला देवी बुटोला

प्रधान

ग्राम पंचायत-कोट

विकासखण्ड.-नारायणबगड

जिला-चमोली

उत्तराखण्ड

निवास-ग्राम-कोट, पोस्ट-कोटुली, वि. ख.-नारायणबगड, जिला-चमोली (उत्तराखण्ड)

मो 9536917116, 08991322029, 9627436174

पत्रांक

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक 15.12.2014

प्रमाणित किया जाता है कि कण्ठरा से कोट केदा/कोट
स्वीकृत 10 किमी 0 मीटर मार्ग जिसका संचालन कोट
वि० गाँव पर करा किया गया उक्त मोटर मार्ग से अधिक ले
आधिक आवादी जुड़ रही है साथ ही दोनों विकास खण्ड
कण्ठप्राग एवं नारायणबगड आपस में जुड़ रहे हैं और
दोनों विकासखण्डों की जनता को पूर्ण आवागमन का
फायदा हो रहा है तथा उक्त मोटर मार्ग में कहीं भी
विवाद की स्थिति नहीं है और पर्यावरण का कम नुकसान
हो रहा है जनहित में उक्त मोटर मार्ग कण्ठप्राग एवं
नारायणबगड, धराली एवं कण्ठप्राग से कोट केदा/कोट
मुख्य मोटर मार्ग बन सकता है दोनों विकासखण्डों का फायदा
देखते हुए उक्त मोटर मार्ग पर अतिशीघ्र कार्यवाही करते
हुए कार्य निर्माण प्रारम्भ करवाया जाय इसमें ग्राम पंचायत
कोट एवं केदा/कोट की किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति
नहीं है



प्रपत्र-23.1

दिनांक 06/02/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	शं. जे. शंकरा देवी	शं. जे. शंकरा देवी
2-	देवी - पत्ता ५	देवी - पत्ता ५
3-	वसन्ती देवी	वसन्ती देवी
4-	दलकी देवी	दलकी देवी
5-	सुनीता देवी	सुनीता देवी
6-	सदानन्द कल्याणसमिति अध्यक्ष	सदानन्द
7-	वचन सिंह पूर्व उप प्रधान	वचन सिंह
8-	शं. जे. शंकरा देवी म. भोगलदल अध्यक्ष	शं. जे. शंकरा देवी
9-	राम लाल - सदस्य क्षेत्र पंचायत - भोटगाणाकई	Ram Lal
		सदस्य क्षेत्र पंचायत भोटगाणाकई
		वि० स्त० नारायणबगड
		जिला चमोली

संयुक्त
वनेपर्वत



ह० / -

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- आ० मुख्यमंत्री छोषा के अन्तर्गत कडारा से केदारकोट मोटर मार्ग
निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कडारा
तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद - चमोली - के अन्तर्गत कडारा से केदारकोट मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (5.320 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे० सिविल सोयम भूमि, अकडिस्थित जल हेतु वन पंचायत भूमि 0.350 हे०) अर्थात् कुल 6.450 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कडारा द्वारा दिनांक 9.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कडारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 6.450 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र-कडारा
विभाग-कर्णप्रयाग (चमोली)



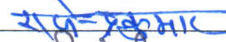
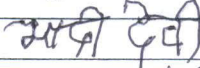
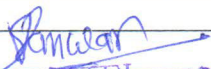
नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 09-2-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कौशरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	अनिल सिंह कण्डारी उप प्रधान	
(2)	राजेंद्र कुमार वाई सदस्य	
(3)	मुन्नी देवी //	
(4)	विशोदा देवी //	
(5)	भादी देवी पंवार	
(6)	जयन्ती देवी	
(7)	नन्दा देवी महिला मंगलदल अध्यक्ष	
	 सर्वेश्वर	
	क्षेत्र पंचायत कण्डारा वि० ख० चर्मसामरा (चमेली)	

संपुत्र
 वनपर्वत
 विशाखा
 मंगलपुर
 मंगलपुर (मंगलपुर)

ह० / -

ग्राम प्रधान

